



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062023-246346
CG-DL-E-07062023-246346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2023/ज्येष्ठ 17, 1945

No. 136]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2023/JYAISHTHA 17, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2023

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी (एसी)-01/2023

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए “फिशिंग नेट” के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का मलेशिया के द्वारा कथित प्रवंचना के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच।

फा.सं. 7/01/2023-डीजीटीआर.— 1. समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे “नियमावली” अथवा “पाटनरोधी नियमावली” भी कहा गया) को ध्यान में रखते हुए:

2. जबकि इंडियन फिशनेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएफएमए) (जिसे आगे “आवेदक” अथवा “आवेदक एसोसिएशन” कहा गया है) ने यह आरोप लगाते हुए समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) तथा समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया

है) की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है कि चीन जन.गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए “फिशिंग नेट” (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” अथवा “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए इन पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना मलेशिया से निर्यात किए गए “फिशिंग नेट” (जिसे आगे “जांच के अधीन उत्पाद” अथवा “पीयूआई” भी कहा गया है) के आयातों के रूप में की जा रही है।

3. जबकि नियम 26 (1) के अन्तर्गत आवेदक द्वारा दायर की गई विधिवत् प्रमाणित आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने संगत पाटनरोधी नियमावली के अनुसार लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की कथित प्रवंचना की मौजूदगी और प्रभाव का निर्धारण करने तथा मलेशिया से “फिशिंग नेट” के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तार की सिफारिश पर विचार करने के लिए दिनांक 21 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. 7/01/2023-डीजीटीआर के माध्यम से जांच की शुरुआत की।

क. मामले की पृष्ठ भूमि

4. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 31 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. 14/44/2016-डीजीएडी (“मूल जांच”) के संदर्भ में चीन जन.गण. और बांग्लादेश के मूल के अथवा वहां निर्यात किए गए “फिशिंग नेट” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” कहा गया है) पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्कों को लगाने की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम जारी किया। तदनुसार, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क दिनांक 10 अप्रैल, 2018 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 20/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) के संदर्भ में लगाया गया था। उक्त शुल्क 5 वर्षों की अवधि के लिए लगाए गए थे।

5. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इंडियन फिशनेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएफएम) द्वारा दायर किए गए आवेदन के अनुसरण में दिनांक 30 सितंबर, 2022 की अधिसूचना सं. 7/22/2022-डीजीटीआर के संदर्भ में चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए “फिशिंग नेट” के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तार के लिए एक निर्णायक समीक्षा की शुरुआत की। इस निर्णायक समीक्षा जांच के निष्कर्ष के लंबित रहने तक, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क जो 9 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाले थे, को दिनांक 6 जनवरी, 2023 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 01/2023-सीमा शुल्क (एडीडी) के संदर्भ में चीन जन.गण. के लिए 3 महीने का आरंभिक समय विस्तार दिया गया था। आगे, 2 महीने का अतिरिक्त समय विस्तार चीन जन.गण. के लिए दिनांक 6 अप्रैल, 2023 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 03/2023-सीमा शुल्क (एडीडी) के संदर्भ में दिया गया था और ये शुल्क 9 सितंबर, 2023 को समाप्त होने वाले थे।

वर्तमान प्रवंचनारोधी जांच

6. जबकि इंडियन फिशनेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएफएम) (जिसे आगे “आवेदक” अथवा “आवेदक एसोसिएशन” कहा गया है) ने यह आरोप लगाते हुए समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क नियमावली, 1995 के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया कि चीन जन.गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए ‘फिशिंग नेट’ (जिसे आगे ‘विचाराधीन उत्पाद’ अथवा ‘पीयूसी’ अथवा ‘संबद्ध वस्तु’ कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना मलेशिया से निर्यात किए गए ‘फिशिंग नेट’ (जिसे आगे ‘जांच के अधीन उत्पाद’ अथवा ‘पीयूआई’ भी कहा गया है) के आयातों के द्वारा की जा रही है।

7. आवेदक एसोसिएशन के 10 सदस्यों (जिसे आगे ‘आवेदक कंपनियां’ कहा गया है) ने वर्तमान प्रवंचना जांच के संबंध में संगत सूचना दायर की है।

8. आवेदक ने सीमा प्रशुल्क नियमावली, 1995 के नियम 25 और 26 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1क) के अनुसार मलेशिया से निर्यात किए गए ‘फिशिंग नेट’ के आयातों तक चीन जन.गण. से ‘फिशिंग नेट’ के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तार का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया है। आवेदक ने यह तर्क दिया कि मौजूदा शुल्कों की प्रवंचना हुई है जिसमें चीन जन.गण. में उत्पादित विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मलेशिया को किया जाता है। तत्पश्चात, इन वस्तुओं को मलेशिया के मूल के तथा भारत को निर्यातित वस्तु के रूप में चीन पर लगाए शुल्कों से प्रवंचना करने के लिए घोषित किया गया है। इस कारण से, यह दावा किया गया है कि यह पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना है, जिसका प्रभाव व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन से स्पष्ट है और इसने घरेलू उद्योग द्वारा महसूस की जा रही पाटनरोधी शुल्कों के उपचारात्मक प्रभावों को नुकसान पहुंचाया है।

ख. प्रक्रिया

9. यहां नीचे वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण संबद्ध जांच के संबंध में किया गया है:

- क. प्राधिकारी ने मलेशिया (जिसे आगे प्रवंचना करने वाला देश भी कहा गया है) से जांच के अधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच¹ की शुरुआत करते हुए दिनांक 21 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. 7/01/2023-डीजीटीआर के संदर्भ में भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक नोट जारी किया।
- ख. प्रवंचनारोधी जांच की शुरुआत के संबंध में डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 5.5 के अंतर्गत भारत में मलेशिया के दूतावास को पूर्व सूचना दी गई थी।
- ग. प्राधिकारी ने आवेदन में उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में मलेशिया के दूतावास, पीयूआई के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को जांच की शुरुआत संबंधी सूचना की एक प्रति अग्रेषित की।
- घ. प्राधिकारी ने पीयूआई के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को पत्र लिखा और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रश्नावली में अपने उत्तर प्रस्तुत करें तथा लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं। निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावलियों की एक प्रति भी निर्धारित समय के भीतर प्राधिकारी को उत्तर देने के लिए इन निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह देने के अनुरोध के साथ ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची के साथ भारत में मलेशिया के दूतावास को भेजे गए थे।
- ङ. प्राधिकारी ने मलेशिया में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा मलेशिया की सरकार को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति भी उपलब्ध कराई। इस आवेदन के गोपनीय रूपांतर की एक प्रति भी सार्वजनिक फाइल के माध्यम से हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोध पर उपलब्ध करायी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए मलेशिया में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावली भेजी:
 - i. जय नेट्स एसडीएन बीएचएन,
 - ii. सेनको फिशिंग नेट इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड,
 - iii. जया एसएंडएम एसडीएन बीएचडी
 - iv. जेसी मशीनरी एसडीएन बीएचडी
 - v. जया बीएमआई ट्रावल सिस्टम्स एसडीएन बीएचडी
 - vi. डीपी होलसेलर एसडीएन बीएचडी
 - vii. वाटर ड्रेगन फिशिंग नेट इंडस्ट्री एसडीएन
 - viii. रेस्क्यू एंगल बिजनेस कन्सलटेंसी,
 - ix. केसन केनानगन एसडीएन बीएचडी
 - x. तियोंग होए एंड कंपनी एसडीएन बीएचडी
 - xi. पायनियर यूएलटी इंटरप्राइज
 - xii. एक्सयूसीएच इंडस्ट्री एम एसडीएन बीएचडी
- छ. प्रवंचना करने वाले देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा जारी की गई निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर का जवाब नहीं दिया है अथवा प्रस्तुत नहीं किया है।
- ज. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों, प्रयोक्ताओं और एसोसिएशनों को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी:

¹ जांच दल में श्री सतीश कुमार, अपर महानिदेशक, श्री सिंह वीर प्रताप, सलाहकार (लागत), श्री नरेश आर्य, संयुक्त निदेशक (लागत), श्री देवेन्द्र सिंह, उप निदेशक (विदेश व्यापार) थे।

1	कलकत्ता फिशनेट कंपनी	2	एंकर इक्विपमेंट एंड स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	गारवेयर वाल रोप्स लिमिटेड	4	सिल्वरसन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
5	डी.के. इंटरप्राइजेज	6	एम.एम. ट्रेडर्स
7	नोटिलस एक्का सिस्टम्स	8	तेजस्वी एक्सपोर्ट्स
9	टाटा ब्लूस्कोप स्टील लिमिटेड	10	बोथारा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
11	नीलकमल लिमिटेड	12	सैमसंग सीएंडटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
13	एंकर ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड	14	फाउंटेनहेड रिटेयल प्राइवेट लिमिटेड
15	डीसीएस हेयर प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	16	ए-1 फेंस प्रोडक्ट्स कं. प्राइवेट लिमिटेड
17	जी इंडिया इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड	18	अनमोल नॉनवोवन
19	होम कलेक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	20	सागर नेट्स
21	गारवेयर वाल रोप्स लिमिटेड	22	केशव यूनिवर्सल
23	प्लानेट इम्पैक्स	24	वीके सिंथेटिक्स
25	कमर ट्रेडिंग कं. (प्रा.) लिमिटेड	26	सैफ ट्रेडिंग कंपनी
27	ऐक निष्ट	28	नाकवा इंटरप्राइजेज
29	फोनिक्स ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	30	गारवेयर वाल रोप्स लिमिटेड
31	पैकेजिंग एसोसिएट्स	32	कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट फिशिंग नेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
33	तमिलनाडु स्माल एंड टिनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन		

- झ. संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर नहीं दिया और न ही उन्होंने प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत किया।
- ज. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे ई-मेल के माध्यम से एक दूसरे के पास अपने अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर का आदान-प्रदान करें।
- ट. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस चरण में संगत मानी गई सीमा तक किए गए अनुरोधों पर इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- ठ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच इस प्रकार के गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को इस जांच के उद्देश्य से गोपनीय के रूप में विचार किया गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- ड. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से उस सीमा तक सूचना मांगी गई थी, जिस सीमा तक उसे आवश्यक समझा गया। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/आंकड़े का सत्यापन उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया तथा इस अंतिम जांच परिणाम के उद्देश्य से, उस पर

विश्वास किया गया। जहां कहीं भी लागू हुआ, आवश्यक संशोधन के साथ केवल इस प्रकार की सत्यापित सूचना पर विश्वास किया गया है।

- ढ. यह सूचना 1 अक्तूबर, 2021 से शुरू होकर 30 सितंबर, 2022 तक (12 महीने) की जांच की अवधि (पीओआई) के लिए की गई थी। क्षति की जांच की अवधि पर विचार 2019-20, 2020-21, 2021-22 की अवधि तथा जांच की अवधि के रूप में किया गया है। आयातों की प्रवृत्ति की जांच व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन की जांच करने के लिए अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए की गई है।
- ण. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से डीजी प्रणाली आंकड़ों पर विश्वास किया है। चूंकि डीजी प्रणाली आंकड़ों में निर्यातकों के नाम तथा भुगतान किए गए शुल्क के विवरण के संबंध में सूचना निहित नहीं है, डीजी प्रणाली आंकड़ों सहित, इस प्रकार की सूचना के संबंध में अन्य वैकल्पिक डाटा बेस का संदर्भ लिया गया था।
- त. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने हेतु 3 मई, 2023 को मौखिक सुनवाई आयोजित की। केवल घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस सुनवाई में भाग नहीं लिया। इस कारण से, घरेलू उद्योग से अनुरोध किया गया था कि वे अपने लिखित अनुरोध 8 मई, 2023 तक प्रस्तुत करें।
- थ. प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है कि वह साक्ष्य के साथ समर्थित हो तथा वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया हो। किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।
- द. इस जांच में आवश्यक तथ्यों वाला एक प्रकटन विवरण जो अंतिम जांच परिणाम का आधार बनता है, इन हितबद्ध पक्षकारों को 30 मई, 2023 को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उसके संबंध में टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए, 1 जून, 2023 तक का समय दिया गया था। प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां घरेलू उद्योग से प्राप्त की गई थी और उन पर उस सीमा तक विचार किया गया है, जिस सीमा तक उसे इस अंतिम जांच परिणाम में संगत माना गया।
- ध. जब कभी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच दिए जाने से इंकार किया है तथा अन्य प्रकार से उसे उपलब्ध नहीं कराया है अथवा इस जांच में काफी हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम को रिकॉर्ड किया है।
- न. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 77.47 रुपए है।
- प. इस अंतिम जांच परिणाम में “***” इस नियमावली के अन्तर्गत गोपनीय आधार पर एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है।

ग. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी), जांच के अधीन उत्पाद (पीयूआई), और समान वस्तु(एलए)

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

10. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और जांच के अधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध दायर नहीं किया।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

11. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और जांच के अधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - क. पूर्व जांच और वर्तमान समीक्षा जांच में शामिल उत्पाद “फिशिंग नेट” है।
 - ख. फिशिंग नेट प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 56 में आता है और इसका आयात उपशीर्ष 5608 1110 के अन्तर्गत किया जाता है। हालांकि, यह वर्गीकरण संसूचक मात्र है तथा वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

- ग. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद और भारत में आयात की गई संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। वे तकनीकी विनिर्देश, गुणवत्ता, कार्य अथवा अंतिम प्रयोगों के मामले में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानापन्न के योग्य हैं। इस कारण से, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पाद को प्रवंचना करने वाले देश से आयात किए गए उत्पाद के समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए।
- घ. मलेशिया के मामले में जांच के अधीन उत्पाद मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यात किया गया 'फिशिंग नेट' (जांच के अधीन उत्पाद अथवा पीयूआई) है। इस वर्गीकरण उपशीर्ष 5608 1110 के अन्तर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 56 के अन्तर्गत किया जाता है और यह वर्तमान जांच में प्रवंचना की वस्तु है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. वर्तमान जांच चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'फिशिंग नेट' के आयातों पर लगाए गए शुल्कों की एक प्रवंचनारोधी जांच है। इस कारण से, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जिसे मूल जांच अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2017 का अंतिम जांच परिणाम में परिभाषित किया गया है जिसे फिर से यहां प्रस्तुत किया गया है:

“8. फिशिंग नेट ग्रिड जैसी संरचना में बुने हुए फाइबर से निर्मित उपकरण हैं। आमतौर पर फिशिंग नेट जाल हैं जिसे अपेक्षाकृत पतले धागे को गांठ बनाकर निर्मित किया जाता है। नाइलोन की तकनीकी विशेषताओं के कारण, नाइलोन फिशनेट पूरे विश्व में खपत की गई कुल फिशनेट का 65-70 प्रतिशत से अधिक है। वर्तमान याचिका में केवल नाइलोन फिशिंग नेट शामिल है चाहे वे 100 प्रतिशत हो अथवा मिश्रित हो। मिश्रित के मामले में, इस कार्य क्षेत्र में वजन से 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक नाइलोन वाले फिशिंग नेट शामिल हैं।

9. इस उत्पाद का कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है। इस उत्पाद का आयात डीजीसीआईएंडएस द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार एचएस कोड 560811 10 के अन्तर्गत किया जा रहा है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण संसूचक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से इस उत्पाद के कार्य क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

10. विचाराधीन उत्पाद को आगे मोनो फिलामेंट यार्न नेट और मल्टीफिलामेंट नेट यार्न में वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनोफिलामेंट नेट का उत्पादन मोनोफिलामेंट यार्न का उपयोग करते हुए किया जाता है। मल्टीफिलामेंट नेट के मामले में मल्टीफिलामेंट यार्न का उपयोग किया जाता है और इस यार्न को सर्वप्रथम ट्विस्ट किया जाता है। उसके बाद, यद्यपि उत्पादन की प्रक्रिया वही है और इसमें तानाबाना नोटिंग, हीट स्ट्रेसिंग, रंजन, एजिन, नार्मलाइजिंग, निरीक्षण और पैकिंग के साथ नेट बनाना शामिल है; मोनोफिलामेंट नेट और मल्टीफिलामेंट नेट का उपयोग फिशिंग में पूर्ण रूप से अलग-अलग क्षेत्रों में होता है। मोनोफिलामेंट नेट का व्यापक रूप से उपयोग अन्तर्देशीय/नदी/झील फिशिंग के लिए किया जाता है और मल्टीफिलामेंट नेट की तुलना में इसकी पारदर्शिता के कारण मछली पकड़ना बेहतर होता है। हालांकि, नेट का जीवनकाल अधिकतम 6 महीने होता है और इस नेट के एक बार क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत मल्टीफिलामेंट नेट का उपयोग बड़ी मछली पकड़ने के लिए तटीय/गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। मल्टीफिलामेंट नेट का जीवनकाल 2 से 2.5 वर्ष का होता है और क्षतिग्रस्त होने पर नेट की मरम्मत की जा सकती है।

11. एचडीपीई फिशिंग नेट और कृषि से संबंधित नेट के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच नाइलोन फिशिंग नेट के पाटन के विरुद्ध है चाहे वह 100 प्रतिशत अथवा मिश्रित नेट हो, जिसमें वजन से 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक नाइलोन होता है। फिशिंग नेट अथवा अन्य नेट के सभी अन्य प्रकार वर्तमान जांच के क्षेत्र से बाहर हैं।”

13. मलेशिया से निर्यात किए गए “फिशिंग नेट” को वर्तमान प्रवंचनारोधी जांच जिसे आगे “जांच के अधीन उत्पाद” अथवा “पीयूआई” कहा गया है, में जांच के अधीन उत्पाद के रूप में माना गया है।

14. प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु मलेशिया से आयात की गई वस्तुओं की ‘समान वस्तु’ हैं। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और मलेशिया से आयात की गई संबद्ध वस्तु रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देश, तकनीकी विनिर्देश, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उद्देश्य, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा इन वस्तुओं का प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानापन्न के योग्य हैं और ग्राहक इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं।

15. वर्तमान प्रवंचनारोधी जांच में, प्राधिकारी ने उपशीर्ष 5608 1110 के अन्तर्गत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 56 के अन्तर्गत वर्गीकृत मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'फिशिंग नेट' के रूप में जांच के अधीन उत्पाद (पीयूआई) माना है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण संसूचक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से संबद्ध जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

16. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र अथवा उसके आधार के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध प्रस्तुत नहीं किए हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

17. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क) दि इंडियन फिशनेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएफएमए) ने इस एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से आवेदन दायर किया है। भारतीय उद्योग एमएसएमई क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और यह बहुत अधिक खंडित है और इस कारण से आवेदक एसोसिएशन ने दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना 09/2021 का पालन करते हुए आवेदन दायर किया है। निर्धारित प्रपत्रों में सभी अपेक्षित सूचना दी गई है।
- ख) इस आवेदन का समर्थन आवेदक एसोसिएशन के सभी सदस्यों द्वारा किया गया है और उन्होंने पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की है। इन सदस्यों ने मलेशिया से पीयूआई के आयातों तक चीन से पीयूसी के आयातों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तार का अनुरोध किया है। 10 आवेदक कंपनियां, जो आवेदक एसोसिएशन के सदस्य हैं, ने इस जांच के उद्देश्य से संगत सूचना प्रदान की है। आवेदक एसोसिएशन के सदस्यों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है।
- ग) प्राधिकारी की कार्य-पद्धति और घरेलू उद्योग के क्षेत्र की समझ तथा पूर्व में की गई प्रवंचनारोधी जांचों में इसके स्थान पर विश्वास किया गया है। दिनांक 19 मार्च, 2019 की बंगलादेश से जूट सैकिंग थैलों के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में, प्राधिकारी ने यह माना कि 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की जांच नियम 26 के अंतर्गत परस्पर लागू नहीं है।
- घ) चीन जन.गण., कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाइलैंड और यूएसए से दिनांक 18 अगस्त, 2017 की कोल्ड रोलड स्टील के संबंध में प्रवंचनारोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम में, यह माना गया था कि 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत जांच प्रवंचना जांचों में परस्पर लागू नहीं हैं। इसके बावजूद, आवेदक स्थान की आवश्यकता को पूरा करता है और पाटनरोधी नियमावली के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. इस आवेदन को मैसर्स इंडियन फिशनेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा इसके सभी सदस्यों की ओर से दायर किया गया है। निम्नलिखित 10 कंपनियों, जो इस एसोसिएशन के सदस्य हैं, ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से अपेक्षित सूचना प्रदान की है:

- i. जसनेट्स
- ii. श्रीमा फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
- iii. स्वास्तिक फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
- iv. बलिगा फिशनेट्स
- v. वसंतम इंडस्ट्रियल सेंटर
- vi. ग्लोबल फिशनेट्स
- vii. वी फिशनेट्स

viii. इंडोनेट्स

ix. कासिम नेट्स

x. बी एंड बी नेट्स

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग एमएसएमई क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और यह बहुत अधिक खंडित है और इस एसोसिएशन के सभी सदस्यों के समर्थन से इस आवेदक संघ द्वारा दायर किया गया आवेदन है।

20. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह आवेदन नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है। हालांकि, यह नोट किया गया है कि 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की जांच नियम 26 के अन्तर्गत आरंभ की गई जांच के लिए परस्पर लागू नहीं है।

ड. प्रवचना का साक्ष्य

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने प्रवचना के साक्ष्य के संबंध में कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

22. प्रवचना के साक्ष्य के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क) मलेशिया से भेजे गए बहुत अधिक आयात के खेप भारतीय बाजार में पाटित मात्राओं में आ रहे हैं तथा इन मात्राओं में आधार वर्ष से जांच की अवधि तक चीन जन.गण. पर शुल्कों के लगाने के बाद वृद्धि हुई है। उसी समय में चीन जन.गण. से प्रत्यक्ष आयात की मात्राओं में काफी हद तक कमी आई।

ख) मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों का चीन की प्रवचना के फलस्वरूप (क) भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से की मांग में कमी; (ख) कीमत में बहुत अधिक कटौती; (ग) बहुत अधिक पाटन मार्जिन; और (घ) भारतीय अर्थव्यवस्था को राजस्व की हानि हुई है।

ग) मलेशिया में जांच के अधीन उत्पाद का एकमात्र ज्ञात उत्पादक अर्थात् जया नेट्स एसडीएन है तथा अन्य सभी केवल निर्यातक/व्यापारी हैं।

घ) मलेशिया में एकमात्र ज्ञात उत्पादक अर्थात् जया नेट्स एसडीएन के पास भारत को निर्यात किए जा रहे जांच के अधीन उत्पाद की इतनी बड़ी भारी मात्रा का उत्पादन करने और निर्यात करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है। प्राधिकारी इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या उक्त उत्पादक जांच के अधीन उत्पाद का 'उत्पादन कर रहा' है अथवा भारत में चीन के मूल के उत्पादों का केवल ट्रांशिपिंग कर रहा है। पहचान की गई अन्य कंपनियां फिशिंग नेट का केवल व्यापारी/निर्यातक हैं और यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि मलेशिया में पीयूआई का कोई अन्य उत्पादक नहीं है।

ड.) सामान्य मूल्य का निर्धारण कच्चे माल की लागत में बदलाव के लिए विधिवत् समायोजित भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर अर्थात् पूर्व में तय किए गए सामान्य मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए।

च) प्रवचना करने वाले देश के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया, जो बहुत अच्छे तरीके से घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों को सिद्ध करता है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों की प्रवचना के संबंध में, इस अधिनियम की धारा 9क(1क) में निम्नलिखित प्रावधान है:

“जहां केंद्र सरकार, ऐसी जांच, जिसे वह आवश्यक समझे, का यह मत है कि उप धारा (1) के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की प्रवचना हुई है, या तो विवरण अथवा नाम अथवा उस वस्तु के संगठन में परिवर्तन करके, जो ऐसे पाटनरोधी शुल्क के अध्याधीन है अथवा ऐसी वस्तु का आयात अनअसेंबल्ड अथवा डिसअसेंबल्ड रूप अथवा उसके मूल देश को बदलकर अथवा निर्यात अथवा किसी अन्य तरीके से किया गया है जिसमें लगाया गया

पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी रखा गया है, वह ऐसी वस्तु अथवा उस देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगा सकती है, जैसी भी स्थिति हो।”

24. पाटनरोधी नियमावली के नियम 25 में निम्नलिखित उल्लेख है:

"25. पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना – (1) प्रवंचना पर किसी परिपाटी, प्रक्रिया अथवा कार्य, जिसके लिए शुल्क लगाए जाने को छोड़कर अपर्याप्त कारण अथवा आर्थिक औचित्य है, के परिणामस्वरूप भारत और उपायों के अध्यक्षीन किसी देश में अलग-अलग कंपनियों के बीच अथवा किसी देश और भारत के बीच व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन के रूप में विचार किया जाएगा; और जहां क्षति का साक्ष्य है अथवा शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव कीमतों अथवा गुणवत्ताओं अथवा समान उत्पाद के दोनों के संदर्भ में कम किए जा रहे हैं, और जहां समान उत्पाद के लिए पूर्व में सिद्ध सामान्य मूल्यों के संबंध में पाटन का साक्ष्य है, यदि उपयुक्त परिवर्तनों अथवा समायोजनों अथवा नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक हो।"

(2) उप नियम (1) में उल्लिखित परिपाटी, प्रक्रिया अथवा कार्य में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन किसी वस्तु का पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित निर्यातक देश अथवा मूल देश सहित किसी भी देश से भारत में अनसेंबलड, अनफिनिशड अथवा इनकम्प्लीट रूप में किया जाता है तथा उसे भारत में अथवा ऐसे देश में असेंबल, फिनिशड अथवा कम्प्लीट किया जाता है तो ऐसी असेंबलिंग, फिनिशिंग अथवा कम्प्लीशन को लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना माना जाएगा, यदि:

- (i) प्रचालन पाटनरोधी जांच के बाद अथवा ठीक उससे पूर्व प्रारंभ किया गया हो अथवा बढ़ाया गया हो तथा हिस्से पुर्जों एवं संघटकों का पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित मूल देश अथवा निर्यातक देश से आयात किया गया हो; और
- (ii) असेंबलिंग, फिनिशिंग अथवा कम्प्लीशन के कार्य के परिणामस्वरूप मूल्य असेंबलड, फिनिशड अथवा कम्प्लीट वस्तु की लागत के 35 प्रतिशत से कम हो।

बशर्ते कि प्रौद्योगिकी की खरीद, यथा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, परामर्शी प्रभार आदि के निमित्त मूल्यवर्धन व्यय के परिकलन में उल्लिखित हिस्से-पुर्जों के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा।

व्याख्या-I – मूल्य का अर्थ असेंबलड, फिनिशड अथवा कम्प्लीट वस्तु की लागत में से आयातित हिस्सों पुर्जों अथवा संघटकों का मूल्य घटाकर

व्याख्या-II – “मूल्य” का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए बौद्धिक संपत्ति अधिकार, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क तथा परामर्शी प्रभारों से संबंधित भुगतानों के निमित्त किए गए खर्चों को हिसाब में नहीं दिया जाएगा।

(ख) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन कोई वस्तु मूल देश से अथवा वस्तु के विवरण, नाम अथवा निर्माण के परिवर्तन में शामिल किसी प्रक्रिया के अध्यक्षीन रखे जाने के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिसूचित निर्यात के देश से भारत में आयात किए जाते हैं, वहां ऐसे परिवर्तन लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के लिए माने जाएंगे, यदि पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन उस वस्तु के विवरण अथवा नाम अथवा निर्माण के परिवर्तन के फलस्वरूप प्रशुल्क वर्गीकरण, यदि कोई है, के अंतर को ध्यान में रखते हुए छोटे रूपों में भी दिखाई देने वाले अथवा उस स्वरूप में वस्तु में परिवर्तन हो रहा है।

(ग) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन कोई वस्तु उस निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा देश के माध्यम से भारत में आयातित की जाती है जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन नहीं है तो ऐसे निर्यात लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के लिए माने जाएंगे, यदि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिसूचित निर्यातक अथवा उत्पादक उस वस्तु की अपनी व्यापार परिपाटी, व्यापार पैटर्न अथवा बिक्री के चैनल में निर्यातकों अथवा उत्पादकों अथवा उस देश के माध्यम से भारत में निर्यातित अपने उत्पादों को देने के लिए परिवर्तन करते हैं जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन नहीं हैं;

(घ) अन्य कोई तरीका जिससे इस प्रकार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी किया गया है।”

25. वर्तमान मामले में, आवेदक ने नियमावली के नियम 25(2)(ग) के प्रावधानों के तहत अर्थात् पाटनरोधी शुल्क के तहत न आने वाले देश के माध्यम से संबद्ध सामानों के आयातों के माध्यम से विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना का आरोप लगाया है। प्राधिकारी ने मलेशिया के माध्यम से निर्यात द्वारा चीन पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों की तथाकथित प्रवंचना की जांच की है। इसकी जांच करने के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त लेनदेन-वार आंकड़ों पर विचार किया है।

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय उत्पादक/निर्यातक विशिष्ट हैं। पाटनरोधी जांच के क्षेत्र में आने वाले उत्पादकों/निर्यातकों को संगत आंकड़े/सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि प्राधिकारी निर्धारण कर सकें। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने प्रवंचना करने वाले देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, उन्हें सलाह दी कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सूचना प्रदान करें। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया के किसी भी निर्यातक ने वर्तमान जांच में उत्तर नहीं दिया है।

27. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना की जांच की है।

ड.4 मलेशिया में सिद्ध नहीं किया गया वास्तविक उत्पादन

28. आवेदक ने उल्लेख किया है कि वह मलेशिया में फिशिंग नेट के केवल एक ज्ञात उत्पादक, अर्थात् जया नेट्स एसडीएन बीएचडी का पता लगाने में सक्षम रहा है, जिसकी वेबसाइट फिशिंग नेट का उत्पादन दर्शाती है। तथापि, यह दावा किया गया था कि उक्त निर्माता के पास इतनी बड़ी क्षमताएं होने की जानकारी नहीं है।

29. आवेदक द्वारा उल्लिखित इस एकमात्र उत्पादक के अलावा, यह दर्शाने के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि मलेशिया में जांचाधीन उत्पाद के उत्पादन में कोई अन्य उत्पादक शामिल है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मलेशिया के किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने मलेशिया के दूतावास और उक्त निर्माता जया नेट्स एसडीएन. बीएचडी सहित इस प्रवंचना जांच की शुरुआत पर उत्तर नहीं दिया। उत्तरों के अभाव को देखते हुए, प्राधिकारी यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि जांच की अवधि के दौरान भारत को किए गए जांचाधीन उत्पाद निर्यात में मलेशिया में उत्पादित सामग्री शामिल है या नहीं। इस प्रकार, मलेशिया में जांचाधीन उत्पाद के उत्पादन के तथ्य को सिद्ध नहीं किया जा सका।

30. इस जांच में निर्यातकों/उत्पादकों और आयातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों से उत्तरों के अभाव को देखते हुए, प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में उपलब्ध अनुरोधों पर विचार किया है।

ड.5 व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन

31. प्राधिकारी ने जांचाधीन उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद के व्यापार पैटर्न में परिवर्तन के लिए निर्धारित मानदंडों की जांच की है, और क्या व्यापार पैटर्न में परिवर्तन आर्थिक औचित्य से हुआ है अथवा क्या नियम 25(1) के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण है।

32. विचाराधीन उत्पाद और जांचाधीन उत्पाद के आयात की मात्रा का विश्लेषण करते हुए वर्ष 2018-19 से जांच की अवधि तक व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन का विश्लेषण किया गया है।

देश	2018- 19	2019- 20	2020- 21	2021 -22	जांच की अवधि
यूओएम	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन
मलेशिया से जांचाधीन उत्पाद के आयात	599	988	1,885	2,533	1,906
चीन से जांचाधीन उत्पाद का आयात	164	6	23	9	6
अन्य देशों से जांचाधीन उत्पाद के आयात	347	459	617	405	312
कुल जोड़	1,110	1,452	2,526	2,947	2,224

33. प्राधिकारी ने नोट किया कि वर्ष 2018-19 के दौरान मलेशिया से आयात कम मात्रा में हुआ था, जो उसके बाद चीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद काफी बढ़ गया और तब से काफी बना हुआ है। तथापि, चीन से आयातों में गिरावट आई है और यह जांच की अवधि में नगण्य है।

34. घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि मूल जांच में मलेशिया से कोई आयात नहीं हुआ था और मूल जांच शुरू होने के बाद आयात मलेशिया से बाजार में आने लगे थे।

35. प्राधिकारी ने नोट किया कि मूल जांच के बाद से मांग में गिरावट आई है। तथापि, मलेशिया से आयात अब उन आयातों से भी अधिक हो गए हैं जो मांग में गिरावट के बावजूद वास्तविक जांच में चीन द्वारा सूचित किए गए थे।

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 जांच की अवधि (ओआई)*	2016-17 जांच की अवधि (ओआई)*	2018- 19	2019- 20	2020- 21	2021 -22	अक्तूबर, 21- सितंबर, 22 जांच की अवधि
यूओएम	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन	मी. टन
मलेशिया से जांचाधीन उत्पाद का आयात	-	-	-	1.57	6.88	599	988	1,885	2,533	1,906
चीन से जांचाधीन उत्पाद का आयात	540	648	779	1,066	1,093	164	6	23	9	6
मांग	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

* मूल मामले में जांच की अवधि अप्रैल, 2015 से सितंबर, 2016 तक 18 माह की अवधि थी।

36. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि चीन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद चीन से मलेशिया तक व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन आया है। जबकि मलेशिया से आयातों में वृद्धि हुई है, चीन से आयातों में गिरावट आई है और संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान नगण्य है।

ड.6 विद्यमान पाटनरोधी उपायों और घरेलू उद्योग पर प्रवंचना के प्रभाव का आकलन

ड.6.1 कम आंके जा रहे उपचारात्मक प्रभाव

37. प्रवंचनारोधी जांच का एक अनिवार्य पहलू यह सुनिश्चित करना है कि क्या पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभावों को कम करके आंका जा रहा है। अतः प्राधिकारी ने जांच की है कि किस तरह और किस हद तक प्रवंचित उत्पाद लगाए गए शुल्क को कम कर रहे हैं और इससे शुल्क को बेकार कर रहे हैं। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या मलेशिया से जांचाधीन उत्पाद के आयातों के कारण बाजार हिस्से और कीमत कटौती के संदर्भ में पाटनरोधी शुल्कों के उपचारात्मक प्रभावों को कम आंका गया है।

ड.6.2 शुल्कों की प्रवंचना का मात्रात्मक प्रभाव

38. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों की मांग के बाजार हिस्से की जांच की है और उसे निम्नानुसार दिया गया है:

मांग में बाजार हिस्सा	यूओएम	2019- 20	2020- 21	2021 -22	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	99	110	123
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	%	***	***	***	***
	सूचकांक	100	94	103	110

अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	97	93	105
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	%	***	***	***	***
	सूचकांक	100	94	89	94
भारतीय उद्योग	मी. टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	97	96	109
भारतीय उद्योग	%	***	***	***	***
	सूचकांक	100	94	92	97
प्रवंचना वाला देश – मलेशिया	मी. टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	191	256	193
प्रवंचना वाला देश – मलेशिया	%	***	***	***	***
	सूचकांक	100	184	244	173
वह देश, जिस पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है – चीन	मी. टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	383	150	101
वह देश, जिस पर पाटनरोधी शुल्क लग रहा है – चीन	%	***	***	***	***
	सूचकांक	100	368	142	90
अन्य देश	मी. टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	135	88	68
अन्य देश	%	***	***	***	***
	सूचकांक	100	129	84	61
कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***
	सूचकांक	100	104	105	112
कुल मांग	%	100%	100%	100%	100%

39. प्राधिकारी ने नोट किया कि वर्ष 2019-20 में मलेशिया का बाजार हिस्सा मात्र ***% था, जो वर्ष 2021-22 में ***% तक बढ़ गया और जांच की अवधि में घटकर 10% हो गया, जबकि भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा जांच की अवधि में ***% से घटकर ***% हो गया। साथ ही, यह भी नोट किया जाता है कि पूरी क्षति अवधि में चीन जन. गण. से आयातों का बाजार हिस्सा नगण्य रहा। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि मूल जांच में मलेशिया से आयात शून्य थे और मलेशिया से जांचाधीन उत्पाद का आयात मूल जांच शुरू होने के बाद ही शुरू हुआ था, जो चीन पर शुल्क लगाए जाने के बाद तेज हो गया था। इस प्रकार, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि शुल्क लगाए जाने के बावजूद, भारतीय उद्योग अपने बाजार हिस्से को पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय उद्योग को समग्र रूप से बाजार हिस्से में और हानियां हुई हैं।

ड.6.3 शुल्कों की प्रवंचना का कीमत प्रभाव

40. कीमतों पर जांचाधीन उत्पाद के आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में प्रवंचित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है। प्राधिकारी ने इसे निम्नानुसार माना है:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
आयात मात्रा	मी. टन	599	988	1,885	2,533	1,906
आयातों की पहुँच कीमत	रु./मी. टन	3,59,039	3,87,220	3,95,322	4,00,897	4,17,217

निवल बिक्री प्राप्ति	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	10-30	10 – 30	10 – 30	10 – 30	10 – 30

41. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान जांचाधीन उत्पाद के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है।

च. पाटन मार्जिन का आकलन

च.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

42. किसी भी निर्यातक ने सामान्य मूल्य के संबंध में कोई टिप्पणी या अनुरोध दायर नहीं किया है। नियमावली के नियम 25 के अनुसार, प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे समान उत्पाद के लिए पूर्व में सिद्ध सामान्य मूल्य (उचित समायोजन के साथ) पर विचार करें, सामान्य मूल्य पूर्व में चीन के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में प्रचालन करने के रूप में चीनी उत्पादकों पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया था। अतः, प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे उपयुक्त परिवर्तनों के साथ पूर्व में निर्धारित सामान्य मूल्य को अपनाएं। चूंकि उक्त सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया था, अतः प्राधिकारी मानते हैं कि समान कानूनी प्रावधानों पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

43. यह नोट किया जाता है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित कीमत के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। आवेदक ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आधार के रूप में थाईलैंड से भारत में आयातों का प्रस्ताव किया है। यह देखा जाता है कि चीन से समान उत्पाद के संबंध में समानांतर चल रही निर्णायक समीक्षा जांच में आवेदक द्वारा समान आधार प्रस्तावित किया गया है। बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित कीमत के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। चूंकि दूसरे विकल्प अर्थात् थाईलैंड से भारत को संबद्ध सामान की आयात कीमत के रूप में भारत सहित तीसरे देश से दूसरे देश को कीमत के संबंध में सूचना उपलब्ध है, अतः प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए थाईलैंड से भारत को आयात कीमत अपनाना उचित मानते हैं। यह नोट किया जाता है कि थाईलैंड में उत्पाद में कोई पाटनरोधी जांच या कोई व्यापार उपचारात्मक उपाय नहीं है और जांच की अवधि में आयात की मात्रा काफी अधिक है।

44. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार की भागीदारी की कमी को देखते हुए, प्राधिकारी ने थाईलैंड से भारत में संबद्ध सामानों की आयात कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। चूंकि उक्त कीमत सीआईएफ स्तर पर है, अतः प्राधिकारी ने सीआईएफ से कारखानागत स्तर पर व्यय के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित करके कारखानागत निर्यात कीमत निर्धारित की है। तदनुसार, निर्धारित सामान्य मूल्य *** है।

च.2 जांचाधीन उत्पाद की निर्यात कीमत

45. प्राधिकारी ने प्रवंचना करने वाले देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, उन्हें सलाह दी कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सूचना प्रदान करें। तथापि, किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने न तो उत्तर दिया और न ही प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर किया। अतः प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है।

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम्स के आंकड़े जांच की अवधि के दौरान जांचाधीन उत्पाद के 1,906 मी. टन के आयात को दर्शाते हैं। डीजी सिस्टम के आंकड़ों से निर्धारित सीआईएफ निर्यात कीमत को कारखानागत स्तर पर निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन

व्यय और अंतर्देशीय भाड़ा प्रभारों के लिए समायोजित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत **4.98 अमेरिकी डॉलर/किग्रा** है।

च.3 जांचाधीन उत्पाद का पाटन मार्जिन

47. कारखानागत स्तर पर इस प्रकार निर्धारित उपर्युक्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर, पाटन मार्जिन निकाला गया है, जो निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	मलेशिया
निर्मित सामान्य मूल्य	अमे. डॉ./कि. ग्रा.	***
निवल निर्यात कीमत	अमे. डॉ./कि. ग्रा.	4.98
पाटन मार्जिन	अमे. डॉ./कि. ग्रा.	***
पाटन मार्जिन	%	***
पाटन मार्जिन	% रेंज	50-70

छ. जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की कमी

48. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की वह मात्रा निर्धारित की है जो मलेशिया से जांचाधीन उत्पाद के आयात पर देय होती। नीचे दी गई तालिका जांचाधीन उत्पाद पर पाटनरोधी उपायों के कम होने की मात्रा निर्धारित करती है:

अवधि	मलेशिया से आयात-मात्रा	पाटनरोधी शुल्क	पाटनरोधी शुल्क	पाटनरोधी शुल्क की राशि	शुल्क का क्षरण	परिवर्तन
	मी. टन	अमे. डॉ./कि. ग्रा.	रु. कि. ग्रा.	लाख रु.	लाख रु.	
2019-20	988	2.19	156.92	1,550	1,550	71.65
2020-21	1,885	2.19	164.74	3,105	3,105	75.22
2021-22	2,533	2.19	165.06	4,181	4,181	75.37
अक्तूबर, 21-सितंबर, 22	1,906	2.19	169.66	3,234	3,234	77.47
क्षति अवधि	7,312	2.19	-	12,070	12,070	

49. यह नोट किया जाता है कि मलेशिया से जांचाधीन उत्पाद के इन आयातों पर वर्ष 2019 - 20 से जांच की अवधि के अंत तक 12,070 लाख रुपये की राशि देय होती, यदि इन आयातों को चीनी मूल के सामानों के रूप में घोषित किया गया होता। तथापि, निर्यातकों ने जांचाधीन उत्पाद को मलेशिया के मूल के होने की घोषणा की और विद्यमान शुल्कों को कम कर रहे हैं।

ज. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां**ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

50. प्रकटन विवरण जारी होने के बाद किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी अथवा अनुरोध दायर नहीं किया है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

51. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित टिप्पणियां दायर की हैं, जो प्रकटन विवरण जारी किए जाने का संकेत देती हैं:

क) लागू पाटनरोधी शुल्क को छोड़कर बिना किसी उचित कारण अथवा औचित्य के व्यापार के पैटर्न में काफी परिवर्तन आया है।

ख) मलेशिया से निर्यातित जांचाधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

ग) मलेशिया से जांचाधीन उत्पाद के निर्यात चीनी मूल के हैं और उन्हें भारत में निर्यात किया जा रहा है, यह झूठा दावा किया जा रहा है कि मलेशिया के मूल के समान हैं।

घ) मलेशिया से संबद्ध सामानों का आयात पाटित कीमतों पर है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं तथा परिणामस्वरूप विद्यमान पाटनरोधी उपायों के उपचारात्मक प्रभावों को कम करके घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

ड) जांचाधीन उत्पाद के मामले में शुल्कों की कमी है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

52. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि अधिकतर अनुरोध पुनरावृत्ति के हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और इस अंतिम जांच परिणाम के संगत पैराओं में उन्हें पर्याप्त रूप से हल कर दिया गया है।

झ. निष्कर्ष

53. वर्तमान जांच शुरू किए जाने और घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों की जांच करने के बाद और उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं:

क. पीयूआई के मामले में एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाए जाने के बाद ट्रेड के पैटर्न में बदलाव आया है, जिसके लिए मौजूदा एंटी-डंपिंग ड्यूटी के अलावा कोई उचित कारण या आर्थिक औचित्य नहीं है। मलेशिया से आयात जो मूल जांच की जांच की अवधि के दौरान नगण्य मात्रा में थे, क्षति अवधि के दौरान काफी बढ़ गए जबकि चीन जन गण से आयातों में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद गिरावट आई और जांच की अवधि में नगण्य है। वास्तव में, मलेशिया से संबद्ध वस्तुओं का आयात वर्तमान जांच की जांच की अवधि में 1.57 एमटी (2015-16) से बढ़कर 1,906 एमटी हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान चीन पीआर से आयात 1066 एमटी से घटकर 6 एमटी हो गया।

ख. चीन पीआर से आयातों में भारी गिरावट के बावजूद, भारतीय उद्योग जो असंगठित, विखंडित हैं और जो एमएसएमई श्रेणी में आते हैं, ने मूल जांच की तुलना में मलेशिया से पीयूआई के आयातों के लिए अपना बाजार हिस्सा खो दिया। मूल जांच की जांच अवधि के दौरान मलेशिया का बाजार हिस्सा नगण्य था जो 2019-20 में 6% और 2021-22 में 13% हो गया। मलेशिया से पीयूआई का आयात वर्तमान जांच की जांच की अवधि में बहुत अधिक है और मूल जांच में चीन से आयात से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप क्षति अवधि के दौरान भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। भारतीय उद्योग चीन पीआर पर मौजूदा शुल्कों के साथ अपने बाजार हिस्से की वसूली करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसे मलेशिया से पीयूआई के आयात के कारण बाजार हिस्सेदारी में नुकसान हुआ था।

- ग. मलेशिया से जांचाधीन उत्पाद के आयात काफी पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में आ रहे हैं और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
- घ. पीयूआई के आयात ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 20/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अप्रैल 2018 द्वारा लगाए गए पीयूसी पर मौजूदा एंटी-डंपिंग उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को कम कर दिया है।
- ड. चूंकि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है, पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क में कमी के कारण वाणिज्यिक लाभ ने पीयूआई का निर्यात करके उत्पादकों/निर्यातकों को लाभान्वित किया है।

क. सिफारिश

54. प्राधिकारी उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 20/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के द्वारा लगाए गए चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों विद्यमान पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के निम्नलिखित के अध्यक्षीन निम्नलिखित जांचाधीन उत्पाद की तालिका में बढ़ाए जाने की सिफारिश करते हैं:

जांचाधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 20/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के माध्यम से चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद अर्थात् "फिशिंग नेट" पर शुल्क की अवधि के साथ होगी।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	उप-शीर्ष***	सामानों का विवरण	विशिष्टताएं	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5608 1110	फिशिंग नेट	कोई भी	मलेशिया	मलेशिया	कोई भी	कोई भी	2.19	कि. ग्रा.	अमे. डॉ.
2	5608 1110	फिशिंग नेट	कोई भी	मलेशिया	कोई भी	कोई भी	कोई भी	2.19	कि. ग्रा.	अमे. डॉ.
3	5608 1110	फिशिंग नेट	कोई भी	मलेशिया और चीन जन. गण. को छोड़कर कोई भी अन्य	मलेशिया	कोई भी	कोई भी	2.19	कि. ग्रा.	अमे. डॉ.

***टिप्पणी - सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है, और पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

55. इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए आयात का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित निर्धारणीय मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9क के तहत शुल्क को छोड़कर सीमा शुल्क के सभी शुल्क शामिल हैं।

ख. आगे की प्रक्रिया

56. इस अंतिम जांच परिणाम के कारण केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष होगी।

अनंत स्वरूप, प्राधिकृत अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th June, 2023

FINAL FINDINGS**Case No. AD (AC) – 01/2023****Subject : Anti-Circumvention investigation concerning alleged circumvention via Malaysia of the anti-dumping duty imposed on imports of “Fishing Net” originating in or exported from China PR.**

F. No. 7/01/2023 – DGTR.—1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as ‘the Rules’ or ‘AD Rules’) thereof –

2. Whereas, Indian Fishnet Manufacturers Association (IFMA) (hereinafter referred to as the “applicant” or “applicant association”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”), alleging that these anti-dumping duties imposed on imports of “fishing net” (hereinafter also referred to as “the product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”) are being circumvented by way of imports of “fishing net” exported from Malaysia (hereinafter also referred to as “the product under investigation” or “PUI”).
3. Whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant under Rule 26 (1), the Authority initiated the investigation vide Notification No. 7/01/2023 – DGTR dated 21st February 2023 to determine the existence and effect of the alleged circumvention of the anti-dumping duty levied and to consider the recommendation of extension of existing anti-dumping duty on imports of “fishing net” from Malaysia, in accordance with relevant AD Rules.

A. BACKGROUND OF THE CASE

4. The Designated Authority vide Notification No. 14/44/2016-DGAD, dated 31st March 2017 (“original investigation”), issued final findings recommending imposition of definitive anti-dumping duties on “fishing net” (hereinafter referred to as the ‘subject goods’ or the ‘the product under consideration’ or the ‘PUC’) originating in or exported from China PR and Bangladesh. Accordingly, definitive anti-dumping duties were imposed vide Customs Notification No. 20/2018-Customs (ADD), dated 10th April 2018. The said duties were levied for a period of 5 years.
5. The Designated Authority initiated a sunset review for extension of the anti-dumping duty imposed on imports of fishing net originating in or exported from China PR vide Notification No. 7/22/2022-DGTR dated 30th September 2022 pursuant to the application filed by Indian Fishnet Manufacturers Association (IFMA). Pending the conclusion of this sunset review investigation, the existing anti-dumping duties, which were due to expire on 09th April 2023, was given an initial extension of 3 months for China PR vide Customs Notification No. 01/2023-Customs (ADD), dated 06th January 2023. Further, an additional extension of 2 months was granted vide Customs Notification No. 03/2023-Customs (ADD), dated 06th April 2023, for China PR, and the duties are due to expire on 09th September 2023.

Present Anti-circumvention investigation

6. Whereas, Indian Fishnet Manufacturers Association (IFMA) (hereinafter referred to as the ‘applicant’ or ‘applicant association’) filed an application before the Authority on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and Customs Tariff Rules, 1995, as amended from time to time, alleging that the anti-dumping duties imposed on imports of “fishing net” (hereinafter referred to as “the product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”) are being circumvented by way of imports of “fishing net” exported from Malaysia (hereinafter also referred to as “the product under investigation” or “PUI”).
7. 10 members of the applicant association (hereinafter referred to as the “applicant companies”) have filed the relevant information with regard to the present circumvention investigation.

8. The applicant filed an application requesting an extension of the anti-dumping duties imposed on the imports of “fishing net” from China PR to the imports of “fishing net” exported from Malaysia, in accordance with Section 9A(1A) of the Customs Tariff Act, 1975 read with Rule 25 and 26 of the Customs Tariff Rules, 1995. The applicant contended that there is a circumvention of existing duties wherein the product under consideration produced in China PR is exported to Malaysia. These goods are thereafter declared as originating in Malaysia and exported to India to circumvent the measures imposed on China. Therefore, it has been claimed that this constitutes circumvention of anti-dumping duty, the effect of which is evident from the change in the pattern of trade, and it has undermined the remedial effects of the anti-dumping duties being felt by the domestic industry.

B. PROCEDURE

9. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
- a. The Authority issued a public notice in the Gazette of India Extraordinary vide Notification No. 7/01/2023–DGTR, dated 21st February 2023, initiating an anti-circumvention investigation¹ concerning imports of the product under investigation from Malaysia (hereinafter also referred to as the circumventing country).
 - b. Prior intimation was given to the Embassy of Malaysia in India under Article 5.5 of the WTO Agreement regarding the initiation of an Anti-Circumvention investigation.
 - c. The Authority forwarded a copy of the initiation notification to the Embassy of Malaysia in India, known exporters/producers of PUI, known importers/users in India, and the domestic industry as per information available in the application.
 - d. The Authority wrote to the known exporters/producers of the PUI and requested them to file their responses in the prescribed questionnaire and make their views known in writing within the time limit prescribed. A copy of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to the Embassy of Malaysia, in India along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers to respond to the Authority within the prescribed time.
 - e. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters in Malaysia and the Government of Malaysia. A copy of the non-confidential version of the application was also made available to the interested parties, on request, through a public file.
 - f. The Authority sent Exporter’s Questionnaire to the following known producers/ exporters in Malaysia to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. Jay Nets SDN BHN,
 - ii. Senco Fishing Net Industries Co. Ltd.,
 - iii. Jaya S&M SDN BHD,
 - iv. JC Machinery SDN BHD,
 - v. Jaya BMI Trawl Systems SDN BHD,
 - vi. DP Wholesale SDN BHD,
 - vii. Water Dragon Fishing Net Industry SDN,
 - viii. Rescue Angel Business Consultancy,
 - ix. Kesan Kenangan SDN BHD,
 - x. Tiong Hoe & Co. SDN BHD,
 - xi. Pioneer Ult Enterprise,
 - xii. Xuch Industry M SDN BHD.
 - g. None of the producers/exporters from the circumventing country have responded or filed the exporter questionnaire response issued by the Authority.
 - h. The Authority sent Importer’s Questionnaires to the following known importers, users, and associations of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

1	Calcutta Fishnet Co.	2	Anchor Equipment and Spares Private Limited
---	----------------------	---	---

¹ The investigation team consisted of Mr. Satish Kumar, ADG, Mr. Singh Veer Pratap, Advisor (Cost), Mr. Naresh Arya, JD (Cost), Mr. Devender Singh, DD (FT)

3	Garware Wall Ropes Ltd.	4	Silverson Overseas Private Limited
5	D.K. Enterprises	6	M. M. Traders
7	Nautilus Aqua Systems	8	Tejasvi Exports
9	Tata Bluescope Steel Limited	10	Bothra Trading Private Limited
11	Nilkamal Limited	12	Samsung C&T India Private Limited
13	Anchor Offshore Services Ltd	14	Fountainhead Retail Private Limited
15	Dcs Hair Products (India) Private Limited	16	A-1 Fence Products Co.Private Limited
17	Ge India Industrial Private Ltd.	18	Anmol Nonwoven
19	Home Collective India Pvt. Ltd.	20	Sagar Nets
21	Garware Wall Ropes Ltd.	22	Keshav Universal
23	Planet Impex	24	V K Synthetics
25	Kamar Trading Co.(P) Ltd.	26	Saif Trading Co.
27	Ek Nisht	28	Naakwa Enterprises
29	Phoenix Trade Ventures Pvt. Ltd.	30	Garware Wall Ropes Limited
31	Packaging Associates	32	Kanyakumari District Fishing Net Manufacturers Association
33	Tamilnadu Small and Tiny Industries Association		

- i. None of the importers/users of the subject goods responded, nor did they file any response to the questionnaire issued by the Authority.
- j. A list of the interested parties was published on the DGTR website. The interested parties were advised to exchange the non-confidential version of their submissions with each other through email.
- k. Submissions made by all the interested parties to the extent considered relevant at this stage have been taken into account in this final findings.
- l. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted, and such information has been considered as confidential for the purpose of this investigation. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide a sufficient non-confidential version of the information filed on a confidential basis.
- m. Information was sought from the domestic industry and other interested parties to the extent deemed necessary. The information/data submitted by the domestic industry has been verified to the extent deemed necessary and relied upon for the purpose of this final findings. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon.
- n. The investigation was carried out for the period of investigation (POI) starting from 01 October 2021 to 30 September 2022 (12 months). The injury examination period has been considered as the period from 2019-20, 2020-21, 2021-22 and the period of the investigation. The trend in imports has been examined for a longer period to examine the change in the pattern of trade.
- o. The Authority has relied upon the DG Systems data for the purpose of the present investigation. Since the DG Systems data does not contain information with regard to names of exporters and details of duty paid, reference was made to other alternative databases with regard to such information, including the DG Systems data.
- p. The Authority held an oral hearing on 03rd May 2023 to provide an opportunity to all the interested parties to present their views orally in accordance with Rule 6(6) of the AD Rules. Only the domestic industry presented its views in the oral hearing, and no other interested party participated in the hearing. Hence, the domestic industry was requested to submit their written submission by 8th May 2023.

- q. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by the domestic industry in this final findings to the extent that the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation. No other interested parties have participated in the present investigation.
- r. A disclosure statement containing the essential facts in this investigation, which forms the basis of the final findings was issued to the interested parties on 30th May 2023 and the interested parties were allowed time up to 1st June 2023 to furnish comments, if any on the same. The comments on the disclosure statement were received from the domestic industry and have been considered, to the extent found relevant in this final findings.
- s. Whenever an interested party has refused access or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present final findings on the basis of the facts available.
- t. The exchange rate adopted by the Authority for the present investigation is as 1 US\$ = **Rs.77.47**.
- u. ‘***’ in this final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC), PRODUCT UNDER INVESTIGATION (PUI), AND LIKE ARTICLE (LA)

C.1 Views of the other interested parties

- 10. None of the interested parties has filed any comment or submissions with regard to the scope of the product under consideration and the product under investigation.

C.2 Views of the domestic industry

- 11. The domestic industry has made the following submission with regard to the scope of the product under consideration and the product under investigation:
 - a. The product involved in the previous investigation and the present review investigation is ‘fishing net’.
 - b. Fishing net falls within Chapter 56 of the Customs Tariff Act, 1975 and is imported under the subheading 5608 1110. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
 - c. There is no known difference between the product manufactured by the domestic industry and the subject goods imported into India. They are comparable in terms of technical specifications, quality, functions, or end-uses. The two are technically and commercially substitutable. Hence, the product manufactured by the domestic industry should be treated as like article to the product imported from the circumventing country.
 - d. The product under investigation in the case of Malaysia is “fishing net” originating in or exported from Malaysia (product under investigation or PUI). It is classified under Chapter 56 of the Customs Tariff Act, 1975, under the subheading 5608 1110, and is the object of circumvention in the present investigation.

C.3 Examination by the Authority

- 12. The present investigation is an anti-circumvention investigation of duties imposed on imports of “fishing net” originating in or exported from China PR. Therefore, the scope of the product under consideration in the present investigation, remains the same as defined in the original investigation, i.e., final findings dated 31st March 2017, which is reproduced herein below –

“8. Fishing Nets are devices made from fibers woven in a grid-like structure. Fishing nets are usually meshes formed by knotting a relatively thin thread. Due to the technical characteristics of Nylon, Nylon fishnet constitutes more than 65-70% of the total fishnet consumption world over. Present petition includes Nylon Fishing nets only whether 100% or blended. In case of blended, scope includes fishing nets containing 50% or more Nylon by weight.

9. The product does not have dedicated customs classification. The product is being imported under HS code, 560811 10 as per the data made available to us by DGC&IS. However, customs classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope.

10. The PUC can be further classified into mono filament yarn net and multifilament yarn net. Monofilament net is produced using monofilament yarn, in case of multifilament net, multifilament yarn is used, and the yarn is first twisted. Thereafter, even though the production process is the same and involves netting with weft & warp knotting, heat stretching, dyeing, aging, normalizing, inspection, and packing; the use of monofilament net and multifilament net is in totally different areas in fishing. Monofilament nets are largely used for inland/river/lake fishing and the catches are better due to its transparency as compared to multifilament net. The life of net is however maximum of 6 months and the net cannot be repaired once damaged. Multifilament nets, on the contrary, are used for coastal/deep sea fishing to catch large fish. Life of multifilament nets is in the region of 2 to 2.5 years and the nets can be repaired when damaged.

11. As regards HDPE Fishing Nets and Agriculture nets, it is noted that the present investigation is against dumping of Nylon Fishing nets, whether 100% or blended nets containing 50% or more Nylon by weight. All other kinds of Fishing nets or other nets are outside the scope of the present investigation."

13. "Fishing net" exported from Malaysia has been considered as the product under investigation in the present anti-circumvention investigation, hereinafter referred to as "the product under investigation" or "PUI".
14. The Authority notes from the information on record that the subject goods produced by the domestic industry are "like article" to the goods imported from Malaysia. The subject goods produced by the Indian industry and imported from Malaysia are comparable in terms of chemical characteristics, product specifications, technical specifications, manufacturing process and technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable, and the customers are using the two interchangeably.
15. In the present anti-circumvention investigation, the Authority has considered the product under investigation (PUI) as "Fishing net" originating in or exported from Malaysia, classified under Chapter 56 of the Customs Tariff Act, under subheading 5608 1110. However, customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the subject investigation.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Submissions made by other interested parties

16. None of the interested parties has filed any comment or submission with regard to the scope of the domestic industry or its standing.

D.2 Submissions made by the domestic industry

17. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and standing:
 - a. The Indian Fishnet Manufacturers Association (IFMA) has filed the application on behalf of the members of the association. The Indian industry falls under the MSME sector and is highly fragmented and hence, the applicant association filed the application adhering to the Trade Notice 09/2021, dated 29th July 2021. All requisite information in the prescribed formats has been provided.
 - b. The application is supported by all members of the applicant association, and they have expressed their concern on the circumvention of the ADD. The members have requested for an extension of the current ADD on imports of the PUC from China to imports of PUI from Malaysia. 10 applicant companies who are members of the applicant association have provided the relevant information for the purpose of this investigation. The production of the members of the applicant association constitutes a major proportion in Indian production.
 - c. Reliance is placed on the Authority's practice and understanding of the scope of the domestic industry and standing in previously conducted anti-circumvention investigations. In the final findings of anti-circumvention investigation concerning anti-dumping duty imposed on imports of Jute sacking bags from Bangladesh dated 19th March 2019, the Authority held that test of 25% and 50% are not *per se* applicable under Rule 26.
 - d. In the final findings of the anti-circumvention investigation concerning cold rolled steel from China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand, and the USA dated 18th August 2017, it was held that test of 25% and 50% are not *per se* applicable in circumvention investigations. Notwithstanding, the applicant satisfies the standing requirement and constitutes the domestic industry within the meaning of the AD Rules.

D.3 Examination by the Authority

18. The application has been filed by M/s Indian Fishnet Manufacturers Association on behalf of all its members. The following 10 companies who are members of the association have provided the requisite information for the purpose of the present investigation:
 - i. Jasnets
 - ii. Sreema Filaments Pvt. Ltd.,
 - iii. Swastik Filaments Pvt. Ltd,
 - iv. Baliga Fishnets
 - v. Vasantham Industrial Centre
 - vi. Global Fishnets
 - vii. Vee Fishnets
 - viii. Indonets

- ix. Kassim Nets
 - x. B & B Nets
19. The Authority notes that the Indian industry falls under the MSME sector and is highly fragmented, and the application filed by the applicant association is with the support of all members of the association.
 20. On the basis of information on record, the Authority notes that the production of the applicant companies constitutes a major proportion in Indian production. The Authority concludes that the applicant constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b). It is, however, noted that the test of 25% and 50% are not *per se* applicable for an investigation initiated under Rule 26.

E. EVIDENCE OF CIRCUMVENTION

E.2 Submissions made by the other interested parties

21. None of the exporters, importers, consumers, and any other interested parties has filed any comment or submission with regard to evidence of circumvention.

E.1 Submissions made by the domestic industry

22. Views of the domestic industry with regard to evidence of circumvention are as follows.
 - a. Significant imports consigned from Malaysia are entering the Indian market at dumped volumes, and these volumes have increased after the imposition of duties on China PR from the base year to the POI. Concurrently the direct import volumes from China PR decreased significantly.
 - b. China's circumvention of existing anti-dumping duties has resulted in (a) loss of the Indian industry's market share in demand; (b) significant price undercutting; (c) significant dumping margin; and (d) loss of revenue to the Indian economy.
 - c. There is only one known producer of the product under investigation in Malaysia, i.e., Jaya Nets Sdn and all others are merely exporters/traders.
 - d. The only known producer in Malaysia, i.e., Jaya Nets Sdn does not have sufficient capacity to produce and export such huge volumes of the product under investigation being exported to India. The Authority may examine whether the said producer is 'producing' the product under investigation or is merely transshipping the Chinese-origin products into India. The other companies identified are merely traders/exporters of fishing net and no evidence is available to show there are any other producers of the PUI in Malaysia.
 - e. The normal value should be determined based on the normal value previously established i.e., based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted for the change in the cost of raw materials.
 - f. None of the exporters/producers from the circumventing country participated in the present investigation, which very well establishes the submissions made by the domestic industry.

E.3 Examination by the Authority

23. With regard to circumvention of the existing anti-dumping duties, Section 9A(1A) of the Act provides as under:

"Where the Central Government, on such inquiry as it may consider necessary, is of the opinion that circumvention of anti-dumping duty imposed under sub-section (l) has taken place, either by altering the description or name or composition of the article subject to such anti-dumping duty or by import of such article in an unassembled or disassembled form or by changing the country of its origin or export or in any other manner, whereby the anti-dumping duty so imposed is rendered ineffective, it may extend the anti-dumping duty to such article or an article originating in or exported from such country, as the case may be."

24. Rule 25 of the Anti-dumping Rules states as follows:

"25. Circumvention of anti-dumping duty.— (1) *Circumvention shall be considered as a change in the pattern of trade between any country and India or between individual companies in any country subject to measures and India, as a result of a practice, process or work for which there is insufficient cause or economic justification other than the imposition of the duty; and where there is evidence of injury or that the remedial effects of the duty are being undermined in terms of the prices or quantities or both of the like product; and where there is evidence of dumping in relation to the normal values previously established for the like product, if necessary with appropriate changes or adjustments or in accordance with the provisions of rule 10.*

(2) *The practice, process or work referred to in the sub-rule (1) includes, inter alia,-*

(a) where an article subject to anti-dumping duty is imported into India from any country including the country of origin or country of export notified for the purposes of levy of anti-dumping duty, in

an unassembled, unfinished or incomplete form and is assembled, finished or completed in India or in any other country, such assembly, finishing or completion shall be considered to circumvent the anti-dumping duty in force if, -

- (i) *the operation started or increased after, or just prior to, the anti-dumping investigations and the parts and components are imported from the country of origin or country of export notified for purposes of levy of anti-dumping duty; and*
- (ii) *the value added to the inputs brought in, during the assembly or completion operation, is less than 35% of the manufacturing cost:*

Provided that for calculation of value addition, expenses on account of procurement of technology, such as patents, copyright, trademark, royalty, technical know-how, consultancy charges, etc., shall not be included in the value of the parts brought in.

Explanation I. – ‘Value’ means the cost of assembled, complete or finished article less value of imported parts or components.

Explanation II. - For the purposes of calculating the ‘value’, expenses on account of payments relating to intellectual property rights, royalty, technical know-how fees and consultancy charges, shall not be taken into account.

- (b) *where an article subject to anti-dumping duty is imported into India from country of origin or country of export notified for the levy of anti-dumping duty after being subjected to any process involving alteration of the description, name or composition of an article, such alteration shall be considered to circumvent the anti-dumping duty in force if the alteration of the description or name or composition of the article subject to anti-dumping duty results in the article being altered in form or appearance even in minor forms regardless of the variation of tariff classification, if any;*
- (c) *where an article subject to anti-dumping duty is imported into India through any exporter or producer or country not subject to anti-dumping duty, such exports shall be considered to circumvent the anti-dumping duty in force if the exporters or producers notified for the levy of anti-dumping duty change their trade practice, pattern of trade or channels of sales of the article in order to have their products exported to India through any exporter or producer or country not subject to anti-dumping duty;*
- (d) *any other manner whereby the anti-dumping duty so imposed is rendered ineffective.”*

25. In the present case, the applicant has alleged circumvention of the existing anti-dumping duties under the provisions of Rule 25(2)(c) of the Rules, that is, through imports of the subject goods through a country not subject to antidumping duty. The Authority has examined the alleged circumvention of existing anti-dumping duties on China via exports through Malaysia. In order to examine the same, the Authority has considered transaction-wise data procured from DG Systems.
26. The Authority notes that the anti-dumping measure is producer/exporter specific. The producers/ exporters subjected to an anti-dumping investigation need to provide relevant data/information so that the Authority can make a determination. Further, the Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the circumventing country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. However, the Authority notes that none of the exporters from Malaysia has responded in the present investigation.
27. In view of the above, the Authority has examined the information available on record before the Authority as filed by the domestic industry.

E.4 Genuine production in Malaysia not established

28. The applicant has stated that it has been able to find only one known producer of fishing net in Malaysia, i.e., Jaya Nets Sdn. Bhd, whose website shows production of fishing net. It was, however, claimed that the said producer is not known to have such huge capacities.
29. Apart from this single producer mentioned by the applicant, there is no information available to show that there are any other producers involved in the production of PUI in Malaysia. The Authority also notes that none of the interested parties from Malaysia responded to the initiation of this circumvention investigation, including the Embassy of Malaysia and the said producer, Jaya Nets Sdn. Bhd. In view of lack of responses, the Authority could not ascertain whether the PUI exports to India made during the POI constitute goods produced in Malaysia. Thus, the fact of production of PUI in Malaysia could not be established.

30. In view of the absence of responses from other interested parties representing the exporters/producers and importers in this investigation, the Authority has considered the submissions available on record.

E.5 Change in Pattern of Trade

31. The Authority has examined the stipulated criteria for a shift in the trade pattern of the PUC to the PUI, and whether a change in trade pattern stemmed from an economic justification or is on account of the levy of anti-dumping duty, in accordance with Rule 25(1).
32. The change in the pattern of trade has been analyzed from 2018-19 to the POI, analyzing the volume of imports of the PUC and the PUI.

Country	2018- 19	2019- 20	2020- 21	2021 -22	POI
UOM	MT	MT	MT	MT	MT
Imports of PUI from Malaysia	599	988	1,885	2,533	1,906
Import of PUC from China	164	6	23	9	6
Import from other countries	347	459	617	405	312
Grand Total	1,110	1,452	2,526	2,947	2,224

33. The Authority noted that imports from Malaysia were in small quantities during 2018 – 19, which increased significantly thereafter following the imposition of anti-dumping duties on China and has since remained significant. However, imports from China have declined and are negligible in the POI.
34. It has been claimed by the domestic industry that there were no imports from Malaysia in the original investigation, and the imports started entering the market from Malaysia after the initiation of the original investigation.
35. The Authority noted that the demand has declined since the original investigation. However, imports from Malaysia are now even more than the imports that were reported by China in the original investigation in absolute terms despite the decline in demand.

Particulars	2012- 13	2013- 14	2014- 15	2015- 16 POI (OI)*	2016- 17 POI (OI)*	2018- 19	2019- 20	2020- 21	2021 - 22	Oct 21- Sept 22 POI
UOM	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT
Imports of PUI from Malaysia	-	-	-	1.57	6.88	599	988	1,885	2,533	1,906
Imports of PUC from China	540	648	779	1,066	1,093	164	6	23	9	6
Demand	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

*POI in the original case was 18 months period from April 2015 to September 2016

36. Based on the foregoing analysis, the Authority concludes that there is a change in the pattern of trade from China to Malaysia after the imposition of anti-dumping duties on China. While imports from Malaysia increased, the imports from China declined and is negligible during the entire injury period.

E.6 Assessment of the effect of circumvention on existing anti-dumping measures and the domestic industry

E.6.1 Remedial effects being undermined

37. An essential aspect of an anti-circumvention investigation is to ascertain whether the remedial effects of the anti-dumping duty imposed earlier are being undermined. The Authority therefore examined the manner in which and to the extent the circumvented products are undermining the duty imposed and thereby rendering such duty as redundant. The Authority has examined whether the remedial effects of anti-dumping duties are undermined in terms of market share and price undercutting due to the imports of the product under investigation from Malaysia.

E.6.2 Volume effect of circumvention of duties

38. The Authority has examined the market share of demand of the subject goods in India and the same is provided as under:

Market Share in Demand	UOM	2019- 20	2020- 21	2021 -22	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>110</i>	<i>123</i>
Sales of Domestic Industry	%	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>94</i>	<i>103</i>	<i>110</i>
Sales of other Indian producers	MT	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>93</i>	<i>105</i>
Sales of other Indian producers	%	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>94</i>	<i>89</i>	<i>94</i>
Indian Industry	MT	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>97</i>	<i>96</i>	<i>109</i>
Indian Industry	%	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>94</i>	<i>92</i>	<i>97</i>
Circumventing country – Malaysia	MT	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>191</i>	<i>256</i>	<i>193</i>
Circumventing country – Malaysia	%	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>184</i>	<i>244</i>	<i>173</i>
Country attracting ADD – China	MT	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>383</i>	<i>150</i>	<i>101</i>
Country attracting ADD – China	%	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>368</i>	<i>142</i>	<i>90</i>
Other Countries	MT	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>135</i>	<i>88</i>	<i>68</i>
Other Countries	%	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>129</i>	<i>84</i>	<i>61</i>
Total Demand	MT	***	***	***	***
	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>105</i>	<i>112</i>
Total Demand	%	100%	100%	100%	100%

39. The Authority noted that Malaysia held a market share of a mere ***% in 2019-20, which increased up to ***% in 2021-22 and declined to 10% in the POI, whereas the market share of the Indian industry declined from ***% to ***% in the POI. At the same time, it is also noted that the market share of imports from China PR remained negligible throughout the entire injury period. The domestic industry submitted that imports from Malaysia were NIL in the original investigation, and imports of PUI from Malaysia started only after the initiation of the original investigation, which intensified after the imposition of duties on China. Thus, the Authority concludes that despite the imposition of duties, the Indian industry has not been able to recover its market share, and rather, the Indian industry as a whole suffered a further loss in market share.

E.6.3 Price effect of the circumvention of duties

40. With regard to the effect of imports of PUI on the prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the circumvented imports as compared to the price of the like products in India. The Authority has considered the same as under:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Import Volume	MT	599	988	1,885	2,533	1,906

Landed price of imports	Rs./MT	3,59,039	3,87,220	3,95,322	4,00,897	4,17,217
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	10-30	10 – 30	10 – 30	10 – 30	10 – 30

41. It is seen that the landed price of imports of the PUI is significantly below the selling price of the domestic industry throughout the injury period.

F. ASSESSMENT OF DUMPING MARGIN

F.1 Determination of Normal Value

42. None of the exporters have filed any comment or submission with regard to normal value. According to Rule 25 of the Rules, the Authority is required to consider the normal value previously established for the like product (with due adjustments). The normal value was previously determined for China, considering Chinese producers as operating in a non-market economy. Therefore, the Authority is required to adopt the normal value previously determined with appropriate changes. Since the said normal value was determined in accordance with Para 7 of Annexure I to the Rules, the Authority considers that the normal value is required to be determined considering the same legal provisions.
43. It is noted that there is no information available on the price or constructed value in a market economy third country. The applicant has proposed imports into India from Thailand as the basis for the determination of normal value. It is seen that the same basis has been proposed by the applicant in the parallel ongoing sunset review investigation relating to the same product from China. There is no information available on the price or constructed value in a market economy third country. Since information is available on the second option, i.e., the price from such a third country to other country, including India, in the form of the import price of the subject goods from Thailand to India, the Authority considers it appropriate to adopt the import price from Thailand to India for the purpose of determination of normal value. It is noted that Thailand has no anti-dumping investigation or any trade remedial measure in the product, and the volume of imports in the POI is significant.
44. In view of the above and considering the lack of participation from any other interested party, the Authority has determined normal value on the basis of the import prices of the subject goods from Thailand to India. Since the said price is at CIF level, the Authority has determined ex-factory export price by appropriately adjusting the same for expenses from CIF to ex-factory level. Accordingly, the normal value determined is ***.

F.2 Export price of the product under investigation

45. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the circumventing country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. However, none of the producers/exporters responded nor filed any responses to the questionnaires. The Authority has hence determined the export price on the basis of the data procured from DG systems data.
46. The Authority notes that the DG systems data shows imports of 1,906 MT of the product under investigation during the POI. The CIF export price determined from DG Systems data has been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses, and inland freight charges on the basis of facts available to determine the export price at the ex-factory level. The net export price so determined is **US\$ 4.98/Kg.**

F.3 Dumping margin of the product under investigation

47. On the basis of the above-stated normal value and export price so determined at the ex-factory level, the dumping margin has thus been worked, which is as follows:

Particulars	Unit	Malaysia
Constructed Normal Value	US\$/Kg	***
Net Export Price	US\$/Kg	4.98
Dumping Margin	US\$/Kg	***
Dumping Margin	%	***
Dumping Margin	% Range	50-70

G. EROSION OF EFFICACY OF EXISTING ANTI-DUMPING DUTY ON PUC DURING POI

48. The Authority has determined the quantum of anti-dumping duty that would have been payable on the imports of the product under investigation from Malaysia. The table below quantifies the amount of erosion of anti-dumping measures on the PUI:

Period	Imports-Quantity from Malaysia	ADD	ADD	ADD amount	Erosion of Duty	Exchange
	MT	USD/kg	Rs. Kg	Rs. Lacs	Rs. Lacs	
2019-20	988	2.19	156.92	1,550	1,550	71.65
2020-21	1,885	2.19	164.74	3,105	3,105	75.22
2021-22	2,533	2.19	165.06	4,181	4,181	75.37
Oct'21-Sep'22	1,906	2.19	169.66	3,234	3,234	77.47
Injury period	7,312	2.19	-	12,070	12,070	

49. It is noted that the amount of **Rs. 12,070 lakhs** would have been payable on these imports of the product under investigation from Malaysia from 2019 – 20 till the end of the period of investigation, had these imports been declared as Chinese-origin goods. However, the exporters declared the PUI as originating in Malaysia and have been eroding the existing duties.

H. POST-DISCLOSURE COMMENTS**H.1 Submissions made by the other interested parties**

50. None of the exporters, importers, consumers, and any other interested parties has filed any comment or submissions, post-issuance of the disclosure statement.

H.2 Submissions made by the domestic industry

51. The domestic industry has filed the following comments, post issuance of the disclosure statement:
- There is a significant change in the pattern of trade without any due cause or justification other than the anti-dumping duty in force.
 - The dumping margin for PUI exported from Malaysia is positive and significant.
 - The exports of the PUI from Malaysia are of Chinese origin and they are being exported to India falsely claiming as goods originating in Malaysia.
 - The imports of the subject goods from Malaysia are at dumped prices and are undercutting the prices of the domestic industry and consequently adversely impacting the domestic industry by undermining the remedial effects of the existing anti-dumping measure.
 - There exists erosion of duties in the case of the PUI.

H.3 Examination by the Authority

52. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the domestic industry and notes that most of the submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in relevant paras of this final findings.

I. CONCLUSION

53. Having initiated the present investigation and after examining the contentions of the domestic industry and the other interested parties and on the basis of the analysis as above, the Authority concludes as under:
- There has been a change in the pattern of trade post imposition of anti-dumping duties in the case of the PUI for which there is no due cause or economic justification other than the existing anti-dumping duties. The imports from Malaysia which were in negligible quantities during the POI of the original investigation increased significantly over the injury period while imports from China PR declined after imposition of anti-dumping duties and is negligible in the POI. In fact, the imports of subject goods from Malaysia increased from 1.57 MT (2015-16) to 1,906 MT in the POI of the present investigation while imports from China PR declined from 1066 MT to 6 MT during the same period.
 - Despite a significant decline in imports from China PR, the Indian industry which are unorganized, fragmented and which falls in the MSME category lost its market share to the imports of PUI from Malaysia compared to the original investigation. Malaysia had an insignificant market share during the POI of the original investigation which increased to 6% in 2019-20 and to 13% in 2021-22. The imports of PUI from Malaysia are very significant in the POI of the present investigation, and is more than the imports from China in the original investigation, resulting in the decline of the market share of Indian industry

during the injury period. The Indian industry was not able to recover its market share with the existing duties on China PR, as it suffered loss in market share due to imports of PUI from Malaysia.

- c. The imports of PUI from Malaysia are entering the Indian market at significantly dumped prices and are undercutting the prices of the domestic industry.
- d. The import of PUI has undermined the remedial effect of the existing anti-dumping measure on the PUC imposed vide Customs Notification No. 20/2018-Customs (ADD) dated 10th April 2018.
- e. Since the dumping margin is above *de minimis*, the commercial gain due to the erosion of anti-dumping duty on the PUC has benefitted producers/exporters by exporting the PUI.

A. RECOMMENDATION

54. The Authority keeping in view the aforesaid, recommends an extension of existing anti-dumping duty on subject goods originating in or exported from China PR, imposed vide Customs Notification No. 20/2018-Customs (ADD), dated 10th April 2018, on PUI tabulated as below, subject to the following:

The validity of the anti-dumping duty on PUI would be co-terminus with the duty on PUC, i.e., “Fishing Net” originating in or exported from China PR, through Customs Notification No. 20/2018-Customs (ADD), dated 10th April 2018.

Duty Table

SN	Sub heading ***	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5608 1110	Fishing Net	Any	Malaysia	Malaysia	Any	Any	2.19	Kg	US Dollar
2	5608 1110	Fishing Net	Any	Malaysia	Any	Any	Any	2.19	Kg	US Dollar
3	5608 1110	Fishing Net	Any	Any other than Malaysia and China PR	Malaysia	Any	Any	2.19	Kg	US Dollar

*****Note** - Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the PUC.

55. The landed value of imports for the purpose of this notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under Sections 3, 3A, 8B, 9A of the said Act.

B. FURTHER PROCEDURE

56. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority